

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—इपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

tfo 361]

मई बिल्ली, शुक्रवार, नवस्थर 5, 1976/कार्तिक 14, 1898

No. 3611

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 5, 1976/KARTIKA 14, 1898

इस भाग में भिन्न पुष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह प्रश्नग संकलन के कप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filled as a separate compilation

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

ORDER

New Delhi, the 5th November 1976

G.S.R. 868(E).—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 359 of the Constitution, the President hereby declares that the right of any person (including a foreigner) to move any court for the enforcement of the rights conferred by article 31 of the Constitution, in so far as they relate to any proceedings, declarations or order or other action or thing taken, made or done, or purporting to have been taken, made or done, under the Tamil Nadu Urban land (Ceiling and Regulation) Act, 1976 (President's Act No. 34 of 1976) and all proceedings pending in any court for the enforcement of the above mentioned rights shall remain suspended for the period during which the Proclamations of Emergency made under clause (1) of article 352 of the Constitution on the 3rd December 1971 and on the 25th June, 1975, are both in force.

By order and in the name of the President

[No. V/11015/25/TN/76-S&P(DV)]

S. S. SIDHU, Addl. Secy

गृह मंत्रालय

ग्रादेश

नई दिल्ली, 5 नवम्बर, 1976

सां का वि 868 (स).—संविधान के अनुच्छेद 359 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शिवतयों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति एतद्द्वारा यह घोषित करते हुँ कि संविधान के अनुच्छेद 31 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन के लिए किसी व्यक्ति (किसी विदेशी सहित) का न्यायालय की सहायता लेने का अधिकार, जहां तक उसका सम्बन्ध तिमलनाडु शहरी भूमि (उच्चतम सीमा और विनियमम) अधिनियम, 1976 (राष्ट्रपति का 1976 का अधिनियम सं 34) के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों घोषणाओं या आदेश या किसी अन्य की गई या की गई मानी जाने वाली कार्यवाहियों घोषणाओं या आदेश या किसी अन्य की गई या की गई मानी जाने वाली कार्यवाहियों संविधान के उपर्युक्त अधिकारियों के प्रवर्तन के लिए किसी न्यायालय में चल रही सभी कार्यवाहियां संविधान के अनुच्छेद 352 के खंड (1) के अधीन 3 दिसम्बर, 1971 और 25 जून, 1975 को की गई आप।त्कालीन स्थित की दोनो घोषणाएं लागु रहने की अवधि में निरस्त रहेंगे।

राष्ट्रपति के ग्रादेश ग्रीर उनके नाम से।

[पं∘ 11015/25/दो० एन०/76-एसएडपी (डी-V)]

एस० एस० सिद्ध, ध्रयर सचिव।